# बैन की राजनीति आईआईटी मद्रास मामला

-योगिता

**यूं तो शासक** वर्ग हमेशा से तार्किक और वैज्ञानिक विचारों से घबराता रहा है। लेकिन मोदी-नीत भाजपा सरकार ने सत्ताशीन होने के बाद से ही जनवादी ताकतों पर चौतरफ़ा हमला बोलना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला आईआईटी मद्रास का है जिसके अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल (एपीएससी) नाम के एक स्टूडेंट ग्रुप को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आई.डी) के हस्तक्षेप के बाद संस्थान ने (नामंजूर) कर दिया। संस्थान के डीन ऑफ़ स्टूडेंट (डीओएस) ने 22 मई को अपने आदेश में, एपीएससी पर संस्थान द्वारा मिले अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उसे बैन कर दिया। उसके बाद से ही पूरे देश की मीडिया व जनवादी तबकों में ये मामला गर्माया है और पूरे देश में जनवादी ताकतों के विरोध के चलते संस्थान को एपीएससी से बैन हटाना पड़ा है। दरअसल डीओएस ने ये कदम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 15 मई को संस्थान को भेजे गये एक पत्र के जवाब में उठाया था। जिसमें आईआईटीएम से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए एपीएससी के खिलाफ़ जांच कर, कार्यवाही करने के आदेश मावन संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटीएम को दिये थे। हुआ यूं कि आईआईटीएम से एक अनाम पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया था जिसमें एपीएससी पर दलित छात्रों को बांटने, उन्हें देश के प्रधानमंत्री मोदी व हिन्दुओं के खिलाफ़ भड़काने का आरोप लगाया गया था।

उसके बाद से ही ये पूरा मामला अस्तित्व में आया। होना तो यह चाहिए था कि एचआरडी को सबसे पहले इस अनाम पत्र की जांच करनी चाहिए थी और उसके बाद आगे की कार्यवाही करनी चाहिए थी पर हुआ ठीक इसका उल्टा। एचआरडी ने अपने स्वभाव के मुताबिक आनन-फ़ानन में एपीएससी के खिलाफ़ जांच के आदेश दे दिये। इससे पहले भी एक फासिस्ट द्वारा आईआईटी में मांस खिलाए जाने की शिकायत करने पर एचआरडी ने आईआईटी में शाकाहारी छात्रों का भोजन अलग पकाने के आदेश दिये थे। इन दोनों ही मामलों में एचआरडी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भाजपा सरकार के फ़ासिस्ट एजेण्डे को लागू करने की कोशिश की। यही एचआरडी शिक्षा के सवाल पर मिलने आए छात्रों व शिक्षकों से मिलने तक से मना कर देता है। देश भर से भेजी जा रही शिकायतों पर चुप्पी साधे रहता है। परंतु उपरोक्त मामले में इसके द्वारा दिखायी गयी तेज़ी इसकी मंशा को जाहिर करती है। दरअसल देश में आईआईटी जैसे संस्थान बुद्धिजीवी छात्रों का केन्द्र बनते हैं जो एक सही दिशा मिलने पर समाज व छात्र-समुदाय अपने साथ खड़ा कर सकते हैं और यही चीज़ मोदी सरकार के लिये खतरनाक है। इसीलिये वह किसी भी तरह की जनवादी और वैज्ञानिक सोच से घबराते हैं। इसीलिए वह भारतीय परिषद, विज्ञान कांग्रेस व शिक्षा संस्थानों का सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। जिससे उनके तथाकथित हिन्दू राष्ट्र पर कोई सवाल न उठा सके। ताज़ा मामला इसका जीता जागता सबूत है।

एपीएससी, आईआईटी मद्रास में दलित व पिछड़े छात्रों का एक ग्रुप है, जो छात्रों के बीच अम्बेडकर-पेरियार से लेकर भगत सिंह के विचारों का प्रचार-प्रसार करता रहा है। 14 अप्रैल 2014 में अपने गठन के बाद से ही ये कृषि, भाषा, श्रम कानूनों में बदलाव से जुड़े सवालों पर अध्ययन चक्र चलाता रहा है। इसी क्रम में वे मोदी सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों की आलोचना भी छात्रों के बीच करता रहा है। जिसके चलते वह लंबे समय से आईआईटी प्रशासन की आंखों में खटक रहा था। पहले भी आईआईटी प्रशासन ने एपीएससी पर अम्बेडकर व पेरियार जैसे राजनीतिक लोग़ों के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर इसकी कार्यवाहियों को रोकने की कोशिश की थी। जबकि इसी संस्थान में 'विवेकानंद' के नाम से एक दक्षिणपंथी स्टडी ग्रुप लंबे समय से काम करता है। परंतु संस्थान को इसके नाम से कोई दिक्कत नहीं है।

एपीएससी पर की गयी उपरोक्त कार्यवाही मोदी-नीत भाजपा सरकार के सामान्य व्यवहार का हिस्सा है। देश के अंदर कई दलितवादी संगठन इसे दलितों के ऊपर हमले के बतौर देखते हैं। और यहीं से इन संगठनों की सीमाएं उज़ागर हो जाती हैं। जबकि पूरे देश के भीतर शैक्षिक संस्थानों में भाजपा सरकार द्वारा यही कोशिश की जा रही है। जरूरत बनती है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का पर्दाफ़ाश कर उसकी हर तानाशाही पूर्ण कार्यवाही का मुंहतोड़ जवाब दिया जाय।

# क्या अंधविश्वास का विरोध नहीं होना चाहिए

चूंकि मेरी कोई सुनता नहीं फिर भी मेरा सुझाव है इस देश में एक राष्ट्रीय आस्था आयोग बने और इसका चेयरमैन मुझे बनाया जाए। मैं तभी ज्वॉइन करूंगा जब ब्लैक कैट कमांडो और बुलेट प्रूफ जैकेट भी दिया जाएगा। तभी मैं बिना किसी राग, द्वेष और भय के कंप्यूटर द्वारा प्रमाणित कर पाऊंगा कि कौन सी बात कहने पर किसकी आस्था भंग हुई और किसकी नहीं।

अखबारों और चैनलों में बंगाली और रूहानी बाबा के विज्ञापनों से तो लगता है कि देश को प्रधानमंत्री नहीं, यही चला रहे हैं। इनके विज्ञापनों से समस्याओं की कुछ कैटगरी इस प्रकार है, पति पत्नी अनबन, लव मैरिज, लव मैरेज खोया प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार ज़रूर संपर्क करें। माता-पिता मनाए भी एक आइटम है और बेटा आपकी बात नहीं मानता है, यह भी एक कैटगरी है। मनचाहा प्यार का समाधान है लेकिन सौतन से छुटकारा दिला देते हैं। किया.कराया भी एक कैटगरी है।

अखबारों के अलावा इनके विज्ञापन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाज़ारों में दिख जाते हैं। ऑटो रिक्शा और माल ढोने वाले टेम्पो के पीछे भी इनका पोस्टर लगा होता है। सार्वजनिक शौचालयों और प्याऊ के ऊपर तो इनका ही पता होता है। ये किसी बंगाली बाबा की वेबसाइट है जो ब्लैक मैजिक का दावा करते हैं। खुद को वशीकरण स्पेशलिस्ट बताने वाले बंगाली बाबा ने अपनी इस साइट पर 17 प्रकार की सेवाओं का ज़िक्र किया है। जैसे जादू टोना, लव प्रॉब्लम और लव वशीकरण। लव वशीकरण इज़ पावरफुल टूल टू अचीव द डिज़ायर्ड पर्सन ऑफ च्वाइस। मतलब आप इसके ज़रिये जिसे पसंद करते हैं वो आपको प्यार करने लगेगा। भाग के जाएगा कहां। वशीकरण के बारे में लिखा है कि वशीकरण एक ऐसी टेकनिक है जिसके इस्तमाल से आप एक आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं और जैसा चाहे उससे वैसा करवा सकते हैं। दो प्रकार के वशीकरण हैं। वशीकरण फॉर गर्ल और वशीकरण फॉर ब्वॉय। बदला और वीज़ा में भी वशीकरण यूज़ होता है।

महाराष्ट्र में दो साल से ब्लैक मैजिक के खिलाफ कानून है। हमारे तमाम न्यूज़ चैनलों पर सुबह सुबह बताया जाता है कि पीला रूमाल लेकर दफ्तर जायेंगे तो आपका बॉस सैलरी बढ़ा देगा और लाल तकिये पर सोयेंगे तो रुका हुआ काम बन जाएगा। एनडीटीवी इंडिया पर इस तरह का कार्यक्रम नहीं आता है। जो भी इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है उसे निशाना क्यों बनाया जाता है।

नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी की हत्या कर दी जाती है। नरेंद्र नायक, जोसेफ , डामराकू, जयंत पांडा इन सबको मारा पीटा जाता है। सभी धर्मों के नाम पर बने संगठन अंधविश्वास के खिलाफ किसी भी अभियान को धर्म के खिलाफ बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि सभी नागरिकों की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, सुधार और जिज्ञासा की भावना का विकास करे। 2011 की जनगणना में 21 लाख लोगों ने खुद को नास्तिक बताया है।

गोवा में हिप्नोथैरपिस्ट कहे जाने वाले डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले सनातन संस्था की स्थापना की है, इन्हें देवता या देवदूत भी कहा जाता है जो हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए साधना कर रहे हैं। इसी संस्था के एक सदस्य समीर गायकवाड को पुलिस ने गोविंद पानसरे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। सनातन संस्था समीर को निर्दोष मानती है और उसकी पैरवी भी कर रही है।

एनडीटीवी इंडिया के सुनील सिंह और सांतिया डूडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सनातन संस्था ने निखिल वाघलेए वरिष्ठ पत्रकार युवराज मोहितेए मराठी दैनिक प्रहार के पत्रकार श्याम सुंदर सोनार को धर्मद्रोही करार दिया है। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन नीजजचरूध्ण्दकजअण्बवउधू पर लिखा है कि पुलिस को संकेत मिले हैं कि पत्रकार निखिल वाघले को मारने की योजना थी। संस्था कहती है कि ऐसी कोई हिटलिस्ट नहीं है। हम लोकतांत्रिक संवाद में यकीन करते हैं। संस्था के दो सदस्य 2008 में मुंबई में हुए तीन धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किये गए थे। दोनों जोधा अकबर फिल्म और एक मराठी नाटक दिखाये जाने के खिलाफ थे। मुंबई की एक अदालत ने दोनों को दस साल की सज़ा सुनाई लेकिन बाद में वो ज़मानत पर रिहा हो गए। अभी ये मामला चल ही रहा है। अक्टूबर 2009 में गोवा में हुए एक स्कूटर धमाके में मारे गए दो लोग कथित रूप से संस्था के सदस्य बताये गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कृष्ण की प्रतिमा के साथ हुए कथित अपमान का बदला लेने के लिए स्कूटर में विस्फोटक ले जाया जा रहा था। आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी हुई जिसमें से तीन फरार हैं। पांच पर्याप्त सबूतों के अभाव में छोड़ दिये गए।

सनातन संस्था की वेबसाइट पर गया तो वहां पर कैसे कपड़े पहनने हैं, बाल कैसे होने चाहिए, त्योहार कैसे मनाए जाएं, यह सब लिखा गया है। आध्यात्म के प्रसार का दावा किया गया है। संस्था ने वेबसाइट पर लंबे बालों वाली महिला का फोटो देते हुए लिखा है कि नारी के लंबे बालों से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे पर्यावरण में शक्ति की तरंगें फैल जाती हैं। आजकल की औरतें जो छोटे बाल रखने लगी हैं उसकी वजह से पूरी मानवता नकारात्मकता की तरफ जा रही है। हिन्दू धर्म में कहा गया है कि नारी को लंबे बाल रखने चाहिए। मर्द को छोटे बाल रखने चाहिए। मर्दों के लंबे बालों से जो तरंगे निकलती हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। सनातन संस्था मानती है कि जो शादियां रजिस्ट्री से होती हैं वो अर्थहीन होती हैं। धार्मिक कर्मकांडों से होने वाली शादी ही सर्वोच्च है। छोटे कपड़े, टाइट जिंस और मल्टी कलर कपड़े नहीं पहनने हैं। काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। वेबसाइट पर बताया गया है कि क्या क्या पहनना है। औरतें ये पहनेंगी और मर्द ये पहनेंगे। इस तरह की बातें आए दिन स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल भी करते रहते हैं।

2011 में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सनातन संस्था पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेज कर केंद्र से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। यूपीए की सरकार ने नहीं किया। मंगलवार को गोवा के बीजेपी के विधायक विष्णु वाग ने हमारे सहयोगी तेजस मेहता से कहा है कि सनातन संस्था एक आतंकवादी समूह है। गोवा सरकार और मोदी सरकार को इसे बैन कर देना चाहिए। विष्णु वाग ने यह भी कहा है कि गोवा सरकार के मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल सनातन संस्था को राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के एक नेता इस संस्था को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। सनातन संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे ने मुंबई मिरर अखबार से कहा है कि प्रतिबंध लगाने से क्या होगा। हम बिना नाम के भी काम करते रहेंगे। वीरेंद्र मराठे ने माना कि अपने साधक को सैनिक प्रशिक्षण देते हैं और संविधान में हिन्दू राष्ट्र लिखा जाना चाहिए। यही भी कहा कि महाराष्ट्र में हमारे एक लाख साधक हैं, हम सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कई देशों से इंटरनेट से जुड़े हैं। हमारे पास घर.घर जाने वाले मज़बूत प्रचारक हैं। हम हिन्दू राष्ट्र की रक्षा का काम करते रहेंगे।

फिर भारतीय सेना क्या करेगी। आईएसआईस में भर्ती होने के आरोप में कुछ मुस्लिम नौजवान सीरिया जाते हुए पकड़े गए हैं तो कुछ हिन्दू नौजवानों पर हिन्दू राष्ट्र के नाम पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राजनीति के कारण ऐसे मामलों की ठोस और पेशेवार जांच नहीं हो पाती है। इनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने में जितना ख़राब रिकॉर्ड बीजेपी का है उससे ज्यादा कांग्रेस का है। कांग्रेस यही सोचती रह जाती है कि ऐक्शन लेंगे तो हिन्दू वोट नाराज़ हो जाएगा और बीजेपी सरकार में ऐसे तमाम संगठन बेलगाम हो जाते हैं यह सोचकर कि हिन्दुओं की सरकार है, कोई कुछ नहीं बोलेगा।

. रविश कुमार

## तुर्की-ब-तुर्की / शिखर पर शोशेबाज-चालबाज

हिन्दी के एक राष्ट्रीय अखबार 'हिन्दुस्तान' ने शिखर समागम के नाम पर लखनऊ में 12 चर्चित शोशेबाजों-चालबाज़ों को देश की प्रगति के प्रतिनिधियों के रूप में 26-27 सितम्बर 2015 को पेश किया। इनमें शामिल थे-अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, समृति ईरानी, राजीव शुक्ला, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अमीश त्रिपाठी, इरफ़ान खान, कंगना रनौत, वीरेन्द्र सहवाग, और गौतम गंभीर। इन 'विभूतियों' ने जो कहा उससे किसी को शक नहीं रहना चाहिये कि शासक की भाषा अंग्रेजी हो या हिन्दी उसके सरोकारों में आम नागरिक हो ही नहीं सकता। मीडिया की भडैती प्रतिस्पर्धा का नमूना तो यह आयोजन था ही।

हमारा कहना है-

- राजनाथ सिंह को देश को महाशक्ति बनाने की पड़ी दिखी। अखिलेश यादव के लिये विकास का मतलब लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे रहा। गडकरी जलपरिवहन को लेकर और ईरानी बच्चों के स्कूल पहुंचने से जुड़े एप्स को लेकर मुग्ध दिखे। ये थे हमारे राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधि जिनके लिये महंगाई, भ्रष्टाचार, रोज़गार, काला धन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के सरोकारों से कुछ लेना-देना नहीं।
- अब आये क्रिकेट प्रशासक और खिलाड़ी। जाहिर है क्रिकेट के अलावा और किसी खेल से जुड़े व्यक्ति इस लायक समझे ही नहीं जाते कि उन्हें ऐसे शीर्ष समागम में बुलाया जाय। राजीव शुक्ला जो बदनाम आईपीएल के मुखिया हैं, की एकमात्र चिंता यही रही कि डालमिया के निधन के बाद नया बोर्ड अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाय। यानी मिल बांट कर लूटने खाने का सिलसिला चलता रहे। सहवाग और गंभीर दोनों भारतीय क्रिकेट के पिटे हुए मोहरे है और वो इससे आगे सोच ही नहीं सकते कि कैसे उनकी भारतीय टीम में वापसी हो। देश के लिये इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है!
- अमीश त्रिपाठी हिन्दुत्व के चहेते उपन्यासकार हैं। उनका कहना है कि बच्चों को विज्ञान व धर्म एक साथ पढाना होगा। यानी मानव जाति के विकास की लाखों करोड़ों वर्ष की गाथा इस नजरिये से पढाई जायेगी कि ईश्वर ने एक दिन में सृष्टि की रचना कर दी थी। जाहिर है अमीश को तो विशेष रूप से अलग से बनाया होगा ताकि वे शिव-राम पर उपन्यास लिख कर मालामाल हो सकें।
- जावेद अख्तर और शबाना आजमी पंचसितारा एक्टिविस्ट छवि के हैं और ऐसे आयोजनों को थोड़ा-थोड़ा जनवादी चेहरा देने में मददगार सिद्ध होते हैं। यह अलग बात है कि इस प्रयास में वे हास्यास्पद भी बन जाते हैं। मसलन, जावेद ने कहा ''बच्चों को आस्थावान बनायें, लेकिन उन्हें यह न बतायें कि तुम्हारा गौड हिन्दु है या मुसिलम।'' अख्तर साहब तो फ़िर आस्था किस में होगी? पूर्व भी चलो और पश्चिम भी! कमर्शियल सिनेमा के सितारों इरफ़ान और कंगना ने फ़िर भी ईमानदारी दिखाते हुए अपनी बात को अपनी फ़िल्मों तक ही सीमित रखा। हलांकि इससे वे भारतीय जन की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि तो नहीं कहे जा सकते। क्या 'हिन्दुस्तान' अखबार के सम्पादकों और मालिकों की मानसिकगुलामी को देशवासी ढोने के लिये बाध्य हैं?

### स्मार्ट सिटी की लफ्फाजी छोड़ कुछ काम करो मंत्री जी

*''स्मार्ट सिटी के लिये सभी नागरिकों को सहयोग करना होगा उन्हें सुविधा पाने के लिये यूजर चार्ज देने की आदत डालनी होगी।'' (28 सितम्बर को ज़िला मुख्यालय के नवनिर्मित मीटिंग हॉल के उद्घाटन अवसर पर हां में हां मिलाने वाले अफ़सरों व श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए उक्त बात स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल ने कही थी।)*

हमारा कहना है:

- कृष्णपाल जी शहर को स्मार्ट बनाने के लिये आप नागरिकों से क्या सहयोग चाहते हैं? शहर की सड़कों व गली मुहल्लों में घूमते आवारा पशुओं को तमाम शहरी पकड़ कर आपके घर पर छोड़ आयें या अपने घरों में बंद करें? उफ़नते सीवरों की सफ़ाई का जो काम आपकी सरकार नहीं कर पा रही उसे सभी नागरिक मिल कर करें?

खुले मैनहोलों के ढक्कन नागरिक खुद अपने पल्ले से लगायें? सड़कों बज़ारों में जगह-जगह सरकार द्वारा कराये जा रहे अतिक्रमणों से अब नागरिक स्वयं निपटें? आये दिन सड़क टूटने जलभराव के लिये जिम्मेवार सरकारी अधिकारियों का गिरेबान खुद नागरिक पकड़ने को निकलें क्या? शहर को सुव्यवस्थित बनाने के लिये बने कायदे कानूनों को बेच खाने वाले अधिकारियों से अब जनता खुद निपटे क्या?

- अच्छी सुविधायें पाने का यूजर चार्ज तो नागरिक बरसों से देते आ रहे हैं। नगर निगम एवं सरकार द्वारा वसूला जाने वाला हज़ारों करोड़ आखिर जा कहां रहा है कृष्णपाल जी, यह ज्यादा गंभीर मामला है? इससे भी गंभीर मामला विकास के नाम पर नगर निगम द्वारा शहर की जायदादें बेच-बेच कर डकार जाना है। न केवल नगर निगम, जनता से सम्बन्धित हर विभाग भ्रष्टाचार व हरामखोरी का पर्याय बन चुका है, उससे निपटने के लिये क्या जनता को सीधे सड़कों पर उतरना पड़ेगा?